RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 23 FEBRUARY 2022 TO 01 MARCH 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 25 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

स्टेट जीएसटी को एक माह के लिए मिले पावर,हाइवे पर फिर शुरू हुई कार्रवाई Page 3

जर्मनी ने रूस के साथ अहम गैस परियोजना को रोका Page 4

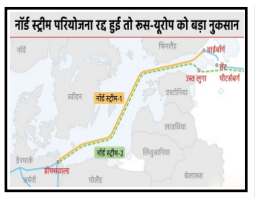

अंतरराष्ट्रीय सेवाएं सामान्य होने के बाद मुंबई हवाईअड्डा रोजाना 'संभालेगा' 1,000 उड़ानें Page 7

editoria!

प्रदूषण का बोझ

अनेक तरह के रसायनों और प्लास्टिक से होनेवाला प्रदूषण जैवविविधता को संकटग्रस्त कर रहा है. इससे पारिस्थितिकी प्रणाली अभूतपूर्व चुनौतियों में घिरती जा रही है. कीटनाशकों के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल से जीव-जंतुओं का जीवन खतरे में है. मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लाये जानेवाले कुछ रसायन हार्मोन सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं. इन रसायनों से वन्यजीवों का विकास, उपापचय और प्रजनन बाधित हो रहा है, जो उनके अस्तित्व के लिए खतरनाक है. वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं कि मानवनिर्मित रसायन और प्लास्टिक कचरा इस ग्रह और मानव जीवन को असहनीय बना रहे हैं. बाजार में लगभग 3.50 लाख प्रकार के उत्पादित रसायन हैं. इसकी बड़ी मात्रा कचरे के रूप में पर्यावरण में पहुंचती है. एक हालिया अध्ययन के अनुसार, आज हम जिन प्रभावों को देख रहे हैं, वे धरती और उसकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण कार्यों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं. रसायनिक प्रदूषकों को रोकने के लिए बड़े स्तर पर प्रयासों की दरकार है. रसायनों और प्लास्टिक कचरों को कम करने जैसे उपायों के साथ वैज्ञानिक अन्य कठोर समाधानों पर जोर दे रहे हैं. अभी तक पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) जैसे उपाय औसत परिणाम ही दे पाये हैं. बीते दो दशकों में प्लास्टिक कचरे का उत्पादन दोगुने से अधिक होकर 367 मिलिटन टन हो गया है, लेकिन, अभी भी 10 प्रतिशत का ही पुनर्चक्रण हो पाता है. साल 2019-20 में भारत में 34 लाख टन प्लास्टिक टन कचरा उत्पन्न हुआ, जिसमें 60 प्रतिशत का ही पुनर्चक्रण हो पाया. एक रिपोर्ट के अनुसार, आज धरती पर प्लास्टिक का कुल वजन सभी जीवित जानवरों के कुल बायोमास का चार गुना से अधिक है. धरती को जीवनोपयोगी बनाये रखने के लिए इन प्रदूषकों पर नियंत्रण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी जैसे सवालों पर संजीदगी से विचार करने की जरूरत है. अगर इन सीमाओं को लांघने की हमारी आदत जारी रही, तो भविष्य में कठोर परिणाम लाजिमी होंगे. प्लास्टिक, एंटीबायोटिक, पेस्टिसाइड्स और गैर-प्राकृतिक धातुओं जैसे मानव निर्मित रासायनिक उत्पादों से स्थिति लगातार बिगड़ रही है. हमें इन जोखिमों के दीर्घकालिक प्रभावों को समझना होगा. हम ज्यादातर रसायनों और उनसे उत्पन्न कचरों की मात्रा या स्थायित्व से अनजान हैं. उनकी विषाक्तता पर्यावरण पर किस हद तक असर कर रही है, इस पर बकायदा अध्ययन-आकलन होना आवश्यक है. वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि विकराल होती इस स्थिति को बदलने के लिए अभी भी हमारे पास वक्त है, बशर्ते कि तत्काल और महत्वाकांक्षी कार्रवाई हेतु उपाय शुरू हों. सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू हुई मुहिम को तेज करने की जरूरत है. हम दुनिया को 'प्लास्टिक प्लेनेट' में नहीं बदल सकते, अतः हमें सामूहिक प्रयत्नों से प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना होगा, ताकि पारिस्थितिकी और जैवविविधता किसी संकट का शिकार न बने.

महंगाई के लिए रहें तैयार, मार्च में भड़क सकता है पेट्रोल-डीजल

अप्रैल में दोगुनी हो जाएगी गैस की कीमत

नई दिल्ली। एजेंसी

मार्च-अप्रैल में देश में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। यूक्रेन-रूस संकट के गहराने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। लेकिन देश में दिवाली के बाद से पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। माना जा रहा है पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही अप्रैल से देश में गैस की कीमतें दोगुना हो सकती हैं। कच्चे तेल एवं गैस के प्रमुख उत्पादक देश रूस के यूक्रेन विवाद में उलझने से आपूर्ति बाधित होने की आशंका की चलते अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड का भाव मंगलवार को 99.38 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। हालांकि, इस वायदा भाव पर कुछ मुनाफावसूली होने से आखिर में यह 98 डॉलर प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर बंद हुआ। इससे पहले ब्रेंट क्रूड सात साल पहले सितंबर 2014 में 99 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर गया था।

कितनी बढ़ सकती है कीमत

सूत्रों के मुताबिक, देश में पेट्रोल एवं डीजल की खुदरा बिक्री दरें 82-83 डॉलर प्रति बैरल के कच्चे तेल भाव के अनुरूप हैं। देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में दिवाली के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे तेल कंपनियों की रोजाना भारी नुकसान हो रहा है। माना जा रहा है कि कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों (झ्रूदत्-अ्गोत्ङ्मे) में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में अभी पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपये और डीजल की कीमत 86.67 रुपये प्रति लीटर है। माना जा रहा है कि इसमें 8 से 10 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो सकता है।

क्रिप्टोकरंसी पर पूर्ण रोक नहीं लगाएगा रूस

8000 डॉलर तक हो सकेगा निवेश

मास्को। एजेंसी

रूस ने क्रिप्टोकरंसी या डिजिटल करंसी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रूस के वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टोकरंसी के नियमन से जुड़ा ड्राफ्ट जमा कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ड्राफ्ट में डिजिटल करंसी के लिए कानूनी बाजार बनाने, डिजिटल करंसी के सर्कुलेशन के लिए नियम बनाने और भागीदारों की सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक, क्रिप्टोकरंसी को केवल निवेश इंस्ट्रूमेंट के तौर पर मंजूरी दी जाएगी।

विदेशी क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज को रूस से लाइसेंस लेना होगा। क्रिप्टोकरंसी की खरीद और बिक्री जैसे कार्य केवल ग्राहक की पहचान के बाद ही होंगे। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह कदम क्रिप्टोकरंसी की गुमनामी को समाप्त कर देगा। ड्राफ्ट में डिजिटल करंसी में निवेश करने वालों के लिए साक्षरता परीक्षण का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस परीक्षण को पास करने के बाद रूसी नागरिक डिजिटल करंसी 6 लाख रूबल या 7,700 डॉलर तक का निवेश कर सकेंगे।

क्रिप्टो के बाद अब एनएफटी पर हैकर्स की नजर

क्रिप्टोकरंसी के बाद अब हैकर्स की नजर नॉन-फंजीबल टोकन (एलएफटी) पर पड़ने लगी है। बीते रविवार को कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि हैकर्स ने एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी को हैक कर लिया है। इसके बदले में हैकर्स में 200 मिलियन डॉलर की राशि वसूली है। हालांकि, ओपनसी के चीफ एक्जीक्यूटिव डेविन फिंजर ने इन दावों को खारिज किया है। ओपनसी पर बीते 30 दिनों में 4.67 लाख से ज्यादा यूजर्स से 2.5 मिलियन से ज्यादा लेनदेन किया है।

क्रिप्टो एसेट्स पर 24% ब्याज देगा काशा

क्रिप्टो से जुड़े नियो बैंक काशा ने व्यक्तिगत वॉलेट लॉन्च किया है। इस वॉलेट में जमा क्रिप्टो एसेट्स पर काशा 24 फीसदी तक का ब्याज देगा। बैंक ने बयान में कहा है कि इस सुविधा के जरिए निवेशक क्रिप्टो एसेट्स को स्टोर करने, खरीदने, बेचने और ब्याज अर्जित करने में सक्षम होंगे। बैंक के अनुसार, निवेशकों को उनके क्रिप्टो एसेट्स पर दैनिक आधार पर ब्याज दी जाएगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई से प्रतिबंधित, अधिसूचना जारी

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

एक जुलाई से मध्यप्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दरअसल इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। जिसके बाद डिस्पोजल आइटम सहित 100 माइक्रोन के कम थिकनेस के बने बैनर-पोस्टर भी प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बोर्ड सचिव एए मिश्रा का कहना है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश में भी अब 1 जुलाई से सिंगल उस प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही इसके आयात भंडारण वितरण और विक्रय पर भी प्रतिबंध लागू किया जाएगा। इस मामले में सचिव का कहना है कि प्लास्टिक बैग सहित ईयर बड में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक आदि सहित कई अन्य प्लास्टिक किक वस्तुओं के निर्माण को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत सिगरेट पैकेट, निमंत्रण पत्र कवर करने वाली पैकिंग, पीवीसी के बैनर तले बनने वाले वस्तुओं को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार की सूचना जारी करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अब इस मामले में कड़े कदम उठा रही है जिसके बाद प्रदेश में स्वच्छता व प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस मामले में कार्यवाही बेहद आवश्यक है। प्लास्टिक कई अर्थों में मानव शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह है वही प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग होने वाले रसायन शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित होते हैं। प्लास्टिक का इंसानों के इम्यून सिस्टम पर प्रभाव पड़ने के अलावा कैंसर, विकलांगता आदि बीमारी सहित बच्चों के विकास पर भी असर पड़ता है।

News यू केन USE

डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे की मजबूती के साथ 74.63 के भाव पर पहुंचा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

रूस-यूक्रेन विवाद पर निवेशकों की करीबी निगाह बनी रहने के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में 21 पैसे की बढ़त के साथ 74.63 रुपया प्रति डॉलर के भाव पर पहुंच गया। अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 74.64 रुपया प्रति डॉलर के मजबूत स्तर पर खुला। कुछ समय बाद यह थोड़ा और बेहतर होकर 74.63 रुपया प्रति डॉलर के भाव पर पहुंच गया। इस तरह पिछले कारोबारी दिवस की तुलना में रुपये में 21 पैसे की मजबूती देखी गई। मंगलवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के खिलाफ 29 पैसे गिरकर 74.84 रुपया प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह मुद्राओं के समूह के खिलाफ डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत बढ़कर 96.06 पर कारोबार कर रहा था। रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक श्रीराम अय्यर ने कहा कि बुधवार को भारतीय मुद्रा की शुरुआत मजबूती से हुई। ब्रेंट क्रूड के भाव में एक दिन पहले की तुलना में आई नरमी से रुपये को समर्थन मिला। हालांकि अधिकांश एशियाई एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं अब भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर बनी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि निवेशकों में फिर से सतर्कता का रुख देखा जा सकता है।

नुमालीगढ़ रिफाइनरी बांस से एथनॉल बनाएगी, फिनलैंड की कंपनी से करार

कोलकाता। एजेंसी

असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) ने बांस से एथनॉल बनाने के लिए फिनलैंड की कंपनी के साथ गठजोड़ किया है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए एनआरएल के प्रबंध निदेशक भास्कर ज्योति फुकन ने कहा कि कंपनी ने जैव-एथनॉल संयंत्र में भारी निवेश किया है। फुकन ने कहा, "हमने बांस से एथनॉल बनाने के लिए फिनलैंड की एक कंपनी के साथ करार किया है। किसानों से बांस की खरीद की जाएगी और संयंत्र एथनॉल के साथ मोटर स्पिरिट के सम्मिश्रण के लिए पूर्वोत्तर में तेल विपणन कंपनियों का 'बैक-अप' आपूर्तिकर्ता बन सकता है।" उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कंपनी कैप्टिव बिजली उत्पादन से बाहर निकलने और ग्रिड से जुड़ने की कोशिश कर रही है जिसके लिए उसने एक हरित बिजली उत्पादक के साथ बिजली खरीद समझौता किया है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल की कीमतों की अस्थिरता से बाहर निकलने की जरूरत है.

कच्चे तेल की कीमत में उछाल के बीच अगले वित्त वर्ष ईंधन की मांग में 5.5 फीसदी तेजी का अनुमान

नई दिल्ली। एजेंसी

एक तरफ कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है, दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण देश में ईंधन की मांग लगातार बढ़ रही है। ऑयल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम प्लानिंग एंड ऐनालिसिस सेल (ईईंप) की रिपोर्ट के मुताबिक, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ देश में ईंधन की मांग एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2022-23 में 5.5 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में ईंधन खपत बढ़कर 21.45 करोड़ टन हो जाने का अनुमान है। मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष में इसके 20.32 करोड़ टन रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2019-20 में देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे ईंधन की खपत 21.41 करोड़ टन थी।चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 4.9 फीसदी बढ़ी। अप्रैल-दिसंबर 2021 में ईंधन खपत 14.83 करोड़ टन रही। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 2020-21 में 19.43 करोड़ टन थी। इस दौरान कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिये 'लॉकडाउन' लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई।

पेट्रोल की खपत 7.8 फीसदी बढ़ने का अनुमान

पीपीएसी के अनुसार, अगले वित्त वर्ष 2022-23 में पेट्रोल की खपत 7.8 फीसदी बढ़कर 3.33 करोड़ टन रहने का अनुमान है। वहीं डीजल की बिक्री 3.9 फीसदी बढ़कर 7.93 करोड़ टन रहने की संभावना है।

विमान ईंधन 49 फीसदी बढ़ने का अनुमान

विमान ईंधन की खपत 2022-23 में 49 फीसदी बढ़कर 76 लाख टन रहने का अनुमान है। हालांकि, यह महामारी-पूर्व स्तर 80 लाख टन से कम है। रसोई गैस (एलपीजी) की मांग अगले वित्त वर्ष में 4.5 फीसदी बढ़कर 2.96 करोड़ टन रहने की संभावना है।

मिट्टी तेल की बिक्री स्थिर रहने का अनुमान

पीपीएसी के मुताबिक, केरोसिन या मिट्टी के तेल की बिक्री 15 लाख टन पर स्थिर रहने जबकि नाफ्था की खपत 3.3 फीसदी बढ़कर 1.5 करोड़ टन हो जाने का अनुमान है। पेटकोक की मांग 2.8 फीसदी बढ़कर 1.48 करोड़ टन पहुंच जाने की संभावना है। वहीं तारकोल की बिक्री 1.8 फीसदी बढ़कर 79 लाख टन रहने का अनुमान है।

यूक्रेन क्राइसिस से महंगा हो रहा है तेल

जैसा कि हम जानते हैं भारत दुनिया का बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। वह अपनी जरूरत का 80 फीसदी तेल आयात करता है। जरूरत का 50 फीसदी गैस भी आयात किया जाता है। रूस-यूक्रेन टेंशन बढ़ने के कारण कच्चे तेल का भाव बढ़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें मंगलवार को 99 डॉलर प्रति बैरल का स्तर पार कर नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। ऑयल मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच भारत ने 82.4 अरब डॉलर का ऑयल इंपोर्ट किया। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बिल में यह 108 फीसदी का उछाल है। वित्त वर्ष 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच भारत ने 39.6 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया था। वित्त वर्ष 2020-21 का टोटल ऑयल इंपोर्ट बिल महज 62.2 बिलियन डॉलर और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यह बिल 101.4 बिलियन डॉलर और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह बिल 112 बिलियन डॉलर था।

भारत में 12-18 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन

DCGI ने CoRevax को दी अंतिम मंजूरी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत सरकार ने 12-18 साल की आयु वर्ग के लिए CoRevax वैक्सीन को अंतिम मंजूरी दे दी है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई (Biological E) के ण्ध्ब्ब्ऊ-19 वैक्सीन CoRevax को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी। बायोलॉजिकल ई. ने जानकारी देते हुए कहा, 'कोविड-19 के खिलाफ भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन (आरबीडी) प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए इस्तेमाल हेतु भारत के दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है।' बता दें कि देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। ऐसे में भारत सरकार ने पिछले साल बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स को मंजूरी दी थी। हालांकि आज इसे अ्ग्उघ की अंतिम मंजूरी भी मिल गई है। ये टीका 12-18 वर्ग के लाभर्थियों को दिया जाएगा। इससे पहले देश में केवल 15-18 साल या उससे ऊपर के लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। ज्ञात हो कि भारत सरकार ने कॉर्बेवैक्स की 5 करोड़ खुराक की खरीद के आदेश दिए हैं। जिसकी कीमत 145 रुपये होगी। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में कोरोना के बूस्टर डोज के लिए हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड की कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी मिली थी। कंपनी की योजना हर महीने 7.5 करोड़ डोज बनाने की है। कंपनी का कहना है कि फरवरी 2022 से वह हर महीने 10 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक का उत्पादन करेगी।

इंडियन ऑयल बेचेगी इस एफएमसीजी कंपनी के प्रोडक्ट, जानिए क्या है मसला

नई दिल्ली। एजेंसी

ऊर्जा क्षेत्र की महारत्न सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल अब घर घर एफएमसीजी प्रोडक्ट भी पहुंचाएगी। ऐसा होगा इंडियन ऑयल के एलपीजी आर्म इंडेन के जरिए। इसके लिए कंपनी ने एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड से समझौता किया है। इंडेन के देश भर में करीब 14 करोड़ ग्राहक हैं। इन ग्राहकों को जिन एलपीजी डीलर से सेवा मिलती है, उन्हीं डीलरों के जरिए ग्राहकों के घर प्रोडक्ट डिलीवर होगा। आईओसी का कहना है उनके डिलीवरीमैन गैस सिलेंडर पहुंचाने ग्राहकों के घर जाते ही हैं। अब वे गैस सिलेंडर के साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट की भी डिलीवरी करेंगे।

हो रहा है सिस्टम का इंटीग्रेशन

इंडियन ऑयल से मिली जानकारी के अनुसार इंडेन के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर डाबर के लिए खुदरा व्यापार भागीदार बनेंगे। वे ग्राहकों को प्रसन्न करने के लिए अपने डिलीवरी कर्मियों के नेटवर्क के माध्यम से करोड़ों इंडेन एलपीजी उपभोक्ता परिवारों को सीधे उत्पादों की संपूर्ण डाबर रेंज बेचने में मदद करेंगे। इसके लिए इंडियन ऑयल और डाबर सिस्टम का इंटीग्रेशना किया जा रहा है।

देश भर में 90 हजार से ज्यादा डिलीवरीमैन

इंडियन ऑयल के ईडी (एलपीजी) एस एस लांबा ने कहा कि कंपनी के इस समय 12,750 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इनके अधीन 90,000 से अधिक डिलीवरीमैन काम कर रहे हैं। ये हर रोज देश के 14.3 करोड़ घरों में सेवा देते हैं। अब वे गैस सिलेंडर के साथ ही डाबर के एफएमसीजी प्रोडक्ट भी ग्राहक के घरों तक पहुंचाएंगे।

भारत में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए अदाणीग्रुप ने बैलार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत और वैंकूवर, कनाडा - अदाणीग्रुप ('Adani'; NSE: ADANIENT)) ने बैलार्ड पावर सिस्टम्स (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP)के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जो भारत में विभिन्न मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल एप्लिकेशंस में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के व्यावसायीकरण के लिए एक संयुक्त निवेश मामले का मूल्यांकन करेगा। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, दोनों पक्ष सहयोग के विभिन्न विकल्पों की जांच करेंगे, जिनमें भारत में फ्यूल सेल निर्माण के लिए संभावित सहयोग शामिल है। ऊर्जा, उद्योग और मोबिलिटी के डीकार्बोनाइजेशन के लिए हाइड्रोजन को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। अदाणी का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा में एक्सीलरेटेड इंवेस्टमेंट के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन उत्पादकों में से एक बनना है। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अदाणी एंटरप्राइजेज की नवगठित सहायक कंपनी, अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएनआईएल) द्वारा संचालित किया जाएगा, जो उन्य कामों के साथ डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स, हरित बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइज़र और विंड टरबाइन के निर्माण सहित हरित हाइड्रोजन (ग्रीन हाइड्रोजन) के उत्पादन पर केंद्रित है। अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएनआईएल)के निदेशक श्री विनीत एस. जैनने कहा कि'हरित हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और फ्यूल सेल्स भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में एक गेम-चेंजर का काम करेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन को सुविधाजनक बनाने में विश्व स्तरीय ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन बनाने की हमारी क्षमता महत्वपूर्ण साबित होगी और हम फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की एक अग्रणी वैश्विक कंपनी, बैलार्ड के साथ साझेदारी करने के लिए उत्साहित हैं, ताकि हम भारत में एक साझा फ्यूल सेल इकोसिस्टम बना सकें। हम फ्यूल सेल ट्रकों, खनन उपकरण, समुद्री जहाजों, ऑफ-रोड वाहनों और महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल पावर के साथ अपने व्यवसायों में इनोवेटिव यूज केसेज को तैनात करेंगे। हम इस रणनीतिक सहयोग के जरिये इंडस्ट्री का विकास करेंगे।'बैलार्ड के प्रेसिडेंट एवं सीईओ श्री रैंडी मैकवेन ने कहा कि 'हम श्री गौतम अदाणी के प्रेरक नेतृत्व और ग्रुप पोर्टफोलियो में अत्यधिक कॉम्प्लिंटरी एसेट्स को देखते हुए अदाणी के साथ साझेदारी करने के लिए उत्साहित हैं। बैलार्ड के लिए भारत विकास के एक नया अवसर देता है, और हम अदाणीग्रुप के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं ताकि उनके एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को समर्थन और गति प्रदान की जा सके।' 1988 में स्थापित अदाणीग्रुप का वर्तमान बाजार पूंजीकरण । 151 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें सात सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं और ये कंपनियां बिजली उत्पादन और वितरण, अक्षय ऊर्जा, गैस एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स (पोर्ट, एयरपोर्ट, शिपिंग और रेल)खनन और संसाधन, और अन्य क्षेत्रों में काम कर रही हैं। बैलार्ड पावर सिस्टम्स का नजरिया एक सस्टेनेबल दुनिया के लिए फ्यूल सेल पावर प्रदान करना है। बैलार्ड जीरो-एमिशन पीईएम फ्यूल सेल्स वर्तमान में बसों, कॉमर्शियल ट्रकों, ट्रेनों, समुद्री जहाजों, पैसेंजर कारों और फोर्कलिफ्ट ट्रकों सहित मोबिलिटी के विद्युतीकरण को सक्षम कर रहे हैं।

उड़ान ने 2021 में भारत के 1000 शहरों में 26 करोड़ से अधिक प्रोडक्ट्स भेजे

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे बड़े बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उड़ान ने घोषणा की कि उन्होंने 15 करोड़ ऑर्डर्स की आपूर्ति करते हुए भारत के 1000 कस्बों और शहरों में 20 लाख टन से अधिक एसेंशियल्स (फ्रेश, एफएमसीजी, स्टेपल्स, फार्मा) और 26 करोड़ प्रोडक्ट्स नॉन-एसेंशियल्स (इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल मर्चेंडाइस और लाइफस्टाइल) श्रेणियों के तहत रवाना किया है। 2021 में प्लेटफॉर्म 5 लाख से अधिक नए दुकानदार / किराना दुकानदार को जोड़ने में सफल रहा है। इस अवधि के दौरान, प्लेटफॉर्म पर 625 से अधिक विक्रेताओं ने 1 करोड़ रूपए प्रत्येक की बिक्री हासिल की।

वर्ष 2021 में उड़ान ने एसेंशियल्स कैटेगरी के बिज़नेस में भारी वृद्धि देखी। प्लेटफॉर्म इस कैटेगरी में 3 लाख से अधिक नए दुकानदारों को जोड़ने में सफल रहा है और 94% से अधिक की पुनरावृत्ति खरीद दर्ज किया। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मांग में 77% की वृद्धि हुई, जिसमें क्रमशः 150 करोड़ बिस्किट के पैकेट्स, 119 करोड़ नमकीन पैकेट्स, 36.5 करोड़ (यूनिट्स) पेय पदार्थ, और उसके बाद खाने के लिए तैयार प्रोडक्ट्स - 116 करोड़ नूडल पैकेट्स और 16 करोड़ चॉकलेट पैकेट्स शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष 2021 में 195 करोड़ पर्सनल केयर और 132 करोड़ होम केयर आइटम्स बेचे गए। इन प्रोडक्ट्स की सबसे अधिक मांग दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान से देखने में आई। स्टेपल्स प्रोडक्ट्स की मांग में वर्ष दर वर्ष 45% की वृद्धि देखी गई, जिसमें 12 लाख टन चीनी तथा तेल और 5 लाख टन चावल, दाल तथा आटा शामिल थे। इन प्रोडक्ट्स की सबसे अधिक मांग दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से देखने में आई।

वर्ष 2021 में उड़ान द्वारा 10 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भेजे गए, जिसमें 8.5 करोड़ से अधिक एक्सेसरीज़ और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, 1 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स और 80 लाख कम्प्यूटर्स तथा आईटी एक्सेसरीज़ शामिल हैं। प्लेटफॉर्म द्वारा कर्नाटक, असम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हेतु बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स देखे गए। जनरल मर्चेंडाइस कैटेगरी के दुकानदारों द्वारा 3 करोड़ से अधिक प्रोडक्ट्स के ऑर्डर दिए गए। इसके तहत 70 लाख मेटल यूटेंसिल्स, 60 लाख क्लीनिंग प्रोडक्ट्स तथा किचन टूल्स, 50 लाख प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, 30 लाख एप्लायंसेस तथा कुकवेयर आइटम्स और 10 लाख साइकल्स, खिलौने तथा बेबी केयर प्रोडक्ट्स की मांग देखने में आई। उड़ान को उत्तर पूर्व राज्यों, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और मध्य प्रदेश से जनरल मर्चेंडाइस आइटम्स के लिए भारी मात्रा में ऑर्डर्स मिले।

उड़ान के लाइफस्टाइल बिज़नेस में कपड़े, एक्सेसरीज़ और फुटवियर शामिल हैं। प्लेटफॉर्म द्वारा वर्ष 2021 में 80 लाख ऑर्डर्स की आपूर्ति के तहत भारत में मौजूद लाइफस्टाइल रिटेलर्स में से 22% रिटेलर्स को 13 करोड़ से अधिक प्रोडक्ट्स भेजे गए। प्लेटफॉर्म ने पूरे भारत में 4 करोड़ से अधिक फेस मास्क्स भेजे, जिसमें 2020 की मांग की तुलना में 60% की वृद्धि दर्ज की गई। 50 लाख से अधिक मास्क्स असम और उत्तर प्रदेश को भेजे गए, जबकि पश्चिम बंगाल, नागालैंड और बिहार में लगभग 1 करोड़ मास्क की संचयी बिक्री देखी गई। इसके अलावा, 90 लाख कम्फर्ट वियर प्रोडक्ट्स, 90 लाख चप्पलें, 80 लाख टी-शर्ट्स और 30 लाख शर्ट्स समूचे भारत में भेजे गए। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की सबसे अधिक मांग मिजोरम से आई, जिसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम का स्थान रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स में 300 विक्रेताओं, लाइफस्टाइल में 200 विक्रेताओं और जनरल मर्चेंडाइस कैटेगरी में 125 विक्रेताओं ने 2021 में 1 करोड़ रूपए से अधिक की बिक्री हासिल की है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स में 300 विक्रेताओं में से 150 ने इस अवधि के दौरान 2 करोड़ रूपए से अधिक की बिक्री हासिल की।

वैभव गुप्ता, को-फाउंडर तथा सीईओ, उड़ान ने कहा, 'जबकि भारत सहित पूरी दुनिया महामारी की दूसरी और तीसरी लहर से प्रभावित थी, उड़ान अपनी ई-कॉमर्स क्षमताओं का लाभ उठाकर आर्थिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करता रहा। पिछले पांच वर्षों में हमने अपनी गहरी क्षमता का निवेश ठोस वितरण नेटवर्क, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, मजबूत सोर्सिंग और उधार देने की क्षमता तथा उन्नत तकनीकी मंच आदि स्थापित करने में किया, जिन्होंने उड़ान को भीड़ से अलग एक अपना स्थान बनाने में योगदान दिया है। प्लेटफॉर्म पर लाखों नए दुकानदार / किराना दुकानदार का शामिल होना, उच्च दोहराव खरीद दर, और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ वितरण साझेदारी, भारी लागत लाभ प्राप्त करने और व्यापार करने में आसानी के प्रमाण हैं, जो उड़ान अपने व्यापारिक भागीदारों को प्रदान करता है। हमें इस क्रांति का नेतृत्व करने पर गर्व है, जिसे हम 'भारत का ई-कॉमर्स' कहते हैं, जो कि भारत के लाखों दुकानदारों / किराना दुकानदारों और छोटे व्यवसायों को लाभान्वित कर रहा है।'

मार्च में बैंकों में रहेगी लंबी छुट्टी, चेक कर लें छुट्टियों की लिस्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

डिजिटल के बढ़ते प्रभाव से आज के दौर में कई ऐसे बैंकिंग काम होते हैं जिनके लिए बैंक के ब्रांच नहीं जाना होता है। हालांकि, चेक क्लियरेंस या ख्म्ण जैसे कुछ जरूरी काम ऐसे होते हैं, जिनके लिए बैंक जाना जरूरी होता है। ऐसे में ग्राहकों को अपने इन आवश्यक कार्यों के लिए बैंक जाने से पहले छुट्टियों की पूरी लिस्ट देख लेना चाहिए। इससे होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। मार्च महीने में साप्ताहिक अवकाश मिलाकर अलग-अलग जोन में कुल 13 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। RBI के मुताबिक, मार्च, 2022 में त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों की वजह से अलग-अलग जोन में कुल सात दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा रविवार को वैसे भी बैंक में कोई कामकाज नहीं होता है। दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं।

1 मार्च (मंगलवार): महाशिवरात्रि के मौके पर जयपुर, जम्मू, कानपुर, अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोच्चि, लखनऊ, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे।

3 मार्च (गुरुवार): लोसार के अवसर पर गंगटोक में बैंकों में छुट्टी।

4 मार्च (शुक्रवार): चपचार कुट के अवसर पर आइजोल में बैंकों में काम-काज नहीं होगा।

6 मार्च (रविवार): रविवार को बैंक बंद।

12 मार्च (शनिवार): महीने का दूसरा शनिवार होने के वजह से बैंक बंद रहेंगे।

13 मार्च (रविवार): रविवार को बैंक बंद।

17 मार्च (गुरुवार): होलिका दहन के चलते कानपुर, लखनऊ, देहरादून और रांची जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

18 मार्च (शुक्रवार): होली/अप्लुर/डोल जात्रा) के मौके पर कोच्चि, कोलकाता, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, इंफाल और तिरुवनंतपुरम को छोड़ अन्य सभी जोन में बैंक बंद रहेंगे।

19 मार्च (शनिवार): होली/याओसांग का दूसरा दिन होने की वजह से भुवनेश्वर,इंफाल और पटना में बैंकों में छुट्टी।

20 मार्च (रविवार): रविवार होने से बैंक बंद।

22 मार्च (मंगलवार): बिहार दिवस के मौके पर पटना जोन में बंद रहेंगे बैंक।

26 मार्च (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार है तो बैंक बंद रहेंगे।

27 मार्च (रविवार): रविवार है तो बैंक में छुट्टी रहेगी।

स्टेट जीएसटी को एक माह के लिए मिले पावर,हाइवे पर फिर शुरू हुई कार्रवाई

ग्वालियर। एजेंसी

स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन टीम को कार्रवाई के पावर मिल गए हैं। यह पावर लंबे समय से नहीं थे, जिस कारण एंटी इवेजन की टीम काम नहीं कर पा रहीं थी। पावर होने की स्थिति में ही यह काम करती हैं, वर्ना अन्य विभागीय कार्य में लगे रहते हैं। यह पावर एक माह के लिए मिले हैं, जिसमें अच्छी कार्रवाई होने की उम्मीद है।

कोरोना की तीसरी लहर के बाद स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन विंग को विभाग की ओर से पावर दे दिए गए हैं। अब एंटी इवेजन के अधिकारी मैदानी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और वाहन पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं हाल ही में स्टेट जीएसटी की टीम ने शिवपुरी में 10 करोड़ 30 लाख रूपये का आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) रिवर्स कराया है। एंटी इवेजन टीम ने यह कार्रवाई की है। शिवपुरी नगर पालिका ने जीएसटी नियमों की अनदेखी की और तकनीकी तौर पर जीएसटी का भुगतान नहीं हुआ। इससे शासन को दस करोड़ तीस लाख का टैक्स रिवर्सल मिला। वहीं बोगस फर्मों की जांच को लेकर भी विभाग सक्रिय है। ऐसी फर्मों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। विभाग ने बताया कि रूटीन प्रोसेस के तहत फर्मों की जांच चलती रहती है, लेकिन विशेष मामला होता है तो अलग से जांच कर ली जाती है। विभाग भौतिक के साथ-साथ अलग-अलग माध्यमों से निगरानी करता है। शिवपुरी नगर पालिका ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में जीएसटी के नियमों का पूरा पालन नहीं किया और तकनीकी रूप से त्रुटि मिली। यह त्रुटि स्टेट जीएसटी की टीम ने जांच के दौरान पकड़ ली। स्टेट जीएसटी के एंटी इवेजन विंग के उपायुक्त यूएस बैस के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। जिसमें अधिकारियों की टीम शामिल रही। आइटीसी रिवर्सल में यह होता है कि किसी उत्पाद या कार्य के दौरान खरीद-बिक्री में आइटीसी नियमों के अनुसार न हो तो टैक्स रिवर्स किया जाता है।

अमेरिकी दबाव के बाद भी रूस के खिलाफ नहीं जा रहा भारत

नई दिल्ली। एजेंसी

यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे रूस को लेकर भारत के नरम रुख पर अमेरिका ने हैरानी जताई है। अमेरिकी मैगजीन इंटरनेशनल अफेयर्स ने अपने एक आर्टिकल में भारत के इस स्टैंड को लेकर चिंता जाहिर की है। अमेरिकी मैगजीन ने कहा है यूरोप समेत दुनिया के तमाम हिस्सों से यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई की निंदा के स्वर उठे हैं, लेकिन भारत ने इस पर चुप्पी ही रखी है। अमेरिकी पत्रिका में कहा गया कि यदि भारत इस मसले पर रूस की निंदा करता है तो इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा और यह साबित होगा कि वह अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को लेकर भविष्य में भी गंभीर रहने वाला है। इसके अलावा वह चीन के स्टैंड से भी अलग नजर आएगा।

मैगजीन में भारत की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि ऐसा लगता है कि वह तिराहे पर खड़ा है। यदि वह अमेरिका का समर्थन करता है तो फिर पुराने दोस्त रूस से नाराजगी का खतरा होगा, जिसके चीन लगातार करीब जा रहा है। इसके अलावा यदि वह रूस के साथ जाता है तो सबसे अहम और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण साथी अमेरिका को खो देगा। वहीं तटस्थता बरतने की स्थिति में दोनों ही देशों की नाराजगी का संकट रहेगा। हालांकि अमेरिकी पत्रिका की यह टिप्पणी भारत के स्टैंड से बेचैनी को दर्शाती है।

रणनीति और फायदा दोनों

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में भारत ने रूस के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की और लगातार यही कहा कि कूटनीतिक तरीके से मसले का हल होना चाहिए। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत इस मसले पर रूस का साथ नहीं देगा और उसके पाले में आ जाएगा। लेकिन चीन और भारत जैसे बड़े देशों के दूरी बनाने से उसके खेमे में बेचैनी दिख रही है। इस बीच अमेरिकी टिप्पणियों के जवाब में 'द हिंदू' के विदेश मामलों के संपादक जॉन स्टैनली की टिप्पणी भी अहम है, जो इसे लोकतंत्र या दमनकारी नीतियों जैसी बहस से अलग राजनीति के तौर पर देखते हैं। अमेरिकी टिप्पणियों का जवाब देते हुए जॉन स्टैनली ने कहा, 'जो लोग रूस के खिलाफ ज्यादा आक्रामक न होने को लेकर भारत पर हमला बोल रहे हैं, वे यह तथ्य भूल जाते हैं कि भारत के रूस के साथ गहरे संबंध हैं। बीते कुछ सालों में ये संबंध और मजबूत हुए हैं। इसके अलावा वह अपने हित के मुताबिक फैसले ले रहा है।' स्टैनली ने वैश्विक राजनीति में डबल स्टैंडर्ड को भी उजागर किया। उन्होंने कहा, 'रूस ने जब क्रीमिया पर हमला किया था और डोनबास को मान्यता दी थी तो तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। लेकिन जब इजरायल ने गोलान पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया तो उसे मान्यता दे दी गई। पूर्वी यरूशलम को भी मान्यता दे दी गई। तुर्की की ओर से सीरिया के एक हिस्से पर कब्जा करने की भी चर्चा नहीं होती। इसलिए वास्तविक राजनीति पर ही चर्चा होनी चाहिए।'

फिर होगी BSNL की बादशाहत, शुरू होने जा रही 4G सर्विस

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड आखिरकार भारत में 4जी सर्विस लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके लिए बीएसएनएल ने ऊएए (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) के साथ साझेदारी की है। फिलहाल BSNL 4G लॉन्च की तारीख का खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन 91मोबाइल्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इंडिपेंडेंस डे 2022 के करीब इसकी शुरुआत कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, बीएसएनएल देशभर में 1 लाख टेलीकॉम टावर्स लगाने जा रही है, जिसमें से 4 हजार टावर्स अकेले बिहार में लगाए जाएंगे।

फिलहाल कंपनी देशभर में सिर्फ 3जी सर्विस ऑफर कर रही है। जबकि रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया काफी समय से 4जी सर्विस दे रही हैं और फिलहाल 5जी के टेस्टिंग चालू है। बीएसएनएल कंज्यूमर मोबिलिटी डायरेक्टर सुशील कुमार मिश्रा के अनुसार 'बीएसएनएल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ मिलकर 4जी सेवाएं पेश करेगी। यह पहली बार होगा जब भारतीय तकनीक का इस्तेमाल 4जी सेवाओं के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, बीएसएनएल ने बिहार में कम से कम 4,000 समेत देश भर में 1 लाख दूरसंचार टावर बनाने की योजना बनाई है। यह दिल्ली और मुंबई में भी अपनी 4जी सेवाएं प्रदान करेगी।' मिश्रा ने बताया कि स्मार्ट टावर्स की जगह बीएसएनएल मोनोपोल्स का इस्तेमाल करेगी, जो सस्ते होने के साथ ज्यादा प्रभावी भी होते हैं। बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या में भी लगाजार इजाफा हो रहा है। अकेले दिसंबर में ही कंपनी ने 11 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले बीएसएनएल के प्लान ज्यादा सस्ते हैं।

जर्मनी ने रूस के साथ अहम गैस परियोजना को रोका

बर्लिन। एजेंसी

रूसी सेना के यूक्रेन में घुसने की खबरों के बीच जर्मनी ने रूस को बड़ा झटका दिया है। जर्मनी ने रूस के साथ जारी अपनी अहम 'नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना को मंगलवार को निलंबित करने का ऐलान किया। जर्मनी द्वारा कहा गया है कि वह यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई का सख्त विरोध करता है। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि रूस का वार्ता की मेज पर लौटना जरूरी है। इस तरह के एकतरफा फैसलों को रोकना पूरी दुनिया की जरूरत है।

रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा

नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना रूस के लिए बेहद अहम है। रूस इस परियोजना के जरिये जर्मनी को अपनी तेल-गैस की सप्लाई दोगुनी करने वाला था। इससे पुतिन सरकार की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होती। कूटनीतिक धाक भी बढ़ती। परियोजना पर रोक से रूस की कमाई पर भी काफी असर पड़ने की संभावना है।

नॉर्ड स्ट्रीम परियोजना रद्द हुई तो रूस-यूरोप को बड़ा नुकसान

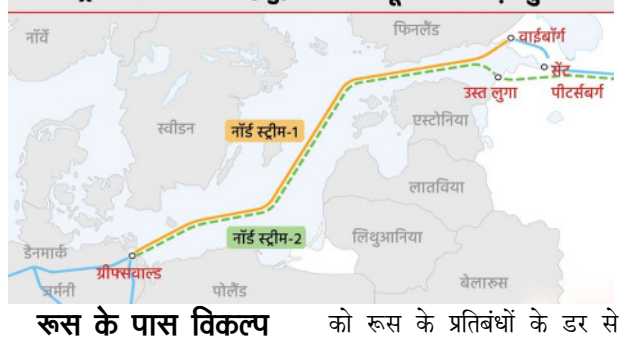

रूस के पास विकल्प

रूस को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तेल-गैस की सप्लाई समुद्री या सड़क मार्ग से करनी होगी, जिसमें उसे काफी आर्थिक नुकसान होगा। इसके साथ ही इससे यूक्रेन को बड़ा फायदा होगा, जो रूस नहीं चाहता।

जर्मनी के लिए परियोजना पर रोक जारी रखना आसान नहीं

रूस फिलहाल यूरोप की कुल ऊर्जा जरूरतों (तेल-गैस) का 40 फीसदी से ज्यादा सप्लाई करता है। जर्मनी में प्रयोग होने वाली आधी प्राकृतिक गैस की सप्लाई रूस से ही होती है। सरकार का लक्ष्य 2045 तक जर्मनी में सभी जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करना है। ऐसे में न चाहते हुए भी जर्मनी को रूस के प्रतिबंधों के डर से उसे आगे परियोजना शुरू करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा।

परियोजना का ये देश करते रहे हैं विरोध

अमेरिका, यूक्रेन और पोलैंड रूस के पाइपलाइन परियोजना का विरोध करते रहे हैं। क्योंकि, फिलहाल रूस ज्यादातर प्राकृतिक गैस की सप्लाई यूक्रेन के रास्ते करता है। हालांकि, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 यूक्रेन से होकर नहीं गुजरती है। इससे रूस को यूक्रेन को कोई भुगतान भी नहीं करना होता है। यूक्रेन को इस प्रोजेक्ट से 2 अरब डॉलर की ट्रांजिट फीस का नुकसान होता है।

यूरोपीय देशों को भी नुकसान होगा

नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट पर अगर रोक लगती है तो इससे जर्मनी के साथ ही बाकी यूरोपीय देशों में भी गैस संकट गहराने का खतरा है, क्योंकि अधिकतर यूरोपीय देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर ही निर्भर हैं। रूस गुस्से में यूरोप को की जाने वाली तेल-गैस की बाकी सप्लाई को रोक कर यूरोपीय देशों के सामने संकट खड़ा कर सकता है।

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन परियोजना पर एक नजर

1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। यह बाल्टिक सागर से होते हुए पश्चिमी रूस से उत्तर-पूर्वी जर्मनी तक जाती है। इस प्रोजेक्ट का मालिकाना हक रूस की सरकारी कंपनी गैजप्रोम के पास है। रूस अभी नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिये जर्मनी को गैस भेजता है। इसकी क्षमता अभी सालाना 55 अरब घन मीटर गैस सप्लाई करने की है। नई पाइपलाइन से यह आपूर्ति दोगुनी हो जाएगी। 83 हजार करोड़ रुपये की लागत आई है इस परियोजना पर, पाइपलाइन का काम सितंबर 2021 में पूरा हो चुका है। कुछ जरूरी मंजूरी के इंतजार में शुभारंभ नहीं हो सका है।

नई नीति से हाइड्रोजन की लागत 40 से 50 प्रतिशत घटेगी : आईओसी

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) कार्बन उत्सर्जन वाली इकाइयों को बदलने के लिए 2024 तक अपनी मथुरा और पानीपत रिफाइनरियों में 'हरित हाइड्रोजन' संयंत्र स्थापित करेगी। कंपनी का मानना है कि हालिया घोषित हरित हाइड्रोजन नीति ऊर्जा बदलाव की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहल है और इससे लागत को कम करने में मदद मिलेगी। आईओसी के निदेशक शोध एवं विकास एस एस वी रामकुमार का कहना है कि नई नीति से हरित हाइड्रोजन के विनिर्माण की लागत में 40-50 प्रतिशत की कटौती होगी।

उन्होंने कहा, ''यह नीति हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सबसे बड़ी 'समर्थक' साबित होगी।'' पेट्रोलियम रिफाइनरियां, उर्वरक संयंत्र और इस्पात इकाइयां तैयार उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रक्रिया में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करती हैं। रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल से अतिरिक्त सल्फर को हटाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। मौजूदा समय में हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस या नेफ्था जैसे जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है और इससे कार्बन उत्सर्जन होता है। आईओसी ने इस 'ग्रे हाइड्रोजन' को 'हरित हाइड्रोजन' से बदलने की योजना बनाई है - जिसे 'स्वच्छ' हाइड्रोजन' भी कहा जाता है। इसमें ऊर्जा का इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों मसलन सौर या पवन से किया जाता है और पानी को इलेक्ट्रोलिसिस (विद्युत अपघटन) प्रक्रिया के जरिये दो हाइड्रोजन कणों और एक ऑक्सीजन कण में बांटा जाता है। रामकुमार ने कहा, ''नवीकरणीय ऊर्जा की दो रुपये प्रति किलोवॉट (या प्रति यूनिट) की मुख्य लागत वास्तव में उत्पादन स्थल (राजस्थान या लद्दाख में सौर फार्म आदि में) की कीमत है। इसे पारेषण लाइनों के जरिये विभिन्न राज्यों में भेजे जाने पर अलग-अलग शुल्क लगते हैं। इसके बाद यह लागत चार से सात रुपये प्रति यूनिट हो जाती है।'' उन्होंने बताया कि कारखाना गेट की लागत चार से सात रुपये प्रति यूनिट पर हरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत 500 रुपये प्रति किलो आती है। वहीं मौजूदा ग्रे हाइड्रोजन में यह सिर्फ 150 रुपये प्रति किलो बैठती है। गत 17 फरवरी को घोषित हाइड्रोजन नीति के तहत हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के खुले इस्तेमाल की छूट होगी और उसपर केंद्रीय अधिभार और अंतर-राज्य पारेषण शुल्क नहीं लगेगा। यह सुविधा 30 जून, 2025 से पहले शुरू होने वाली परियोजनाओं पर मिलेगी। रामकुमार ने कहा कि इससे आवश्यक रूप से हरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत में 40 से 50 प्रतिशत की कमी आएगी।

यूएई के साथ हुए आर्थिक समझौते से भारत को क्या-क्या फ़ायदे

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच का कारोबार 100 अरब डॉलर के पार ले जाने के लिए दोनों देशों के बीच शुक्रवार 18 फ़रवरी को एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए गए। दोनों देशों के बीच हुआ यह समझौता एक 'व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता' (सीईपीए) है। यह भारत का किसी भी अरब देश (मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देश) से हुई पहली सीईपीए संधि भी है।

सीईपीए संधि के तहत सामानों का कारोबार बढ़ाने के साथ सेवाओं का व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया जाता है। इसके लिए टैरिफ़ (कस्टम और आयात शुल्क) कम करने के अलावा व्यापार के रास्ते में आने वाली अड़चनें दूर करने पर ज़ोर रहता है। भारत और यूएई के बीच हुआ यह सीईपीए इस लिहाज से खास है कि इसके लिए दोनों देशों ने काफ़ी तेज़ी से बातचीत की प्रक्रिया पूरी की। इसे महज़ 88 दिनों में पूरा किया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। दुनिया में अभी तक किसी भी सीईपीए को इतने कम समय में अंज़ाम नहीं दिया जा सका है।

पांच साल में व्यापार ढाई गुना करने का लक्ष्य

यूएई के साथ भारत का कारोबार नए मुक़ाम तक ले जाने के लिए इस समझौते में रक्षा, ऊर्जा, जलवायु और डिजिटल व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के इंतज़ाम किए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौक़े पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख़ मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ एक संयुक्त वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'बाज़ार तक पहुंच बढ़ने से अगले 5 सालों में, दोनों देशों के बीच सामानों का द्विपक्षीय कारोबार 100 अरब डॉलर और सेवाओं का कारोबार 15 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है।' इस तरह, दोनों देशों के बीच हुए इस व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते का महत्व यह है कि इसके ज़रिए अगले पांच साल में दोनों देशों के बीच सामानों का व्यापार ढाई गुना तो सेवाओं का व्यापार दो गुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

फ़िलहाल यूएई, भारत का तीसरा और भारत, यूएई का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। 2021 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार क़रीब 43 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें भारत का निर्यात 17 अरब डॉलर रहा, तो आयात 26 अरब डॉलर का हुआ। भारत द्वारा बड़े पैमाने पर मंगाए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के चलते व्यापार का यह संतुलन अभी यूएई के पक्ष में झुका है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के निर्यातकों के बड़े तबके के लिए यूएई एक अच्छा रास्ता है और अब वे पश्चिम एशिया के देशों, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकेंगे।''

भारत इस समय ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसराइल जैसे कई और देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने के लिए बातचीत कर रहा है। माना जा रहा है कि यूएई के साथ हुए इस समझौते से बाक़ी समझौतों को भी गति मिलेगी। इस समझौते को लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत के पूर्व दूत जयंत दासगुप्ता ने कहा, 'खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के सदस्य भी इसी तरह की सीईपीए संधि करना चाहते हैं। यूएई के साथ यह संधि हो जाने के बाद पूरी संभावना है कि जीसीसी से भी बातचीत तेज़ होगी और अगले 6 महीने में यह पूरी हो जाएगी। ऐसा होने पर भारत की पहुंच खाड़ी के सभी देशों तक हो जाएगी। मालूम हो कि खाड़ी सहयोग परिषद में यूएई के अलावा सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान और क़तर सहित कुल छह देश हैं।

किन सेक्टरों को मिलेगा फ़ायदा

इस संधि के बाद, भारत से होने वाले निर्यात के क़रीब 90 फ़ीसदी सामान पर यूएई आयात शुल्क घटा देगा। फ़िलहाल यूएई भारत से आने वाले सामान पर 5 फ़ीसदी का आयात शुल्क लगाता है। इस सौदे में निर्यातकों और कारोबारियों को किसी खास उत्पाद की मात्रा में आने वाली अचानक उछाल से बचाने के लिए एक स्थायी सुरक्षा तंत्र का भी इंतज़ाम किया गया है। इस संधि की वजह से आयात शुल्क घटने और पश्चिम एशिया के बाज़ार मिलने से भारत के रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़े के सामान, खाद्य उत्पाद, कृषि और मेडिकल उत्पाद उद्योगों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है।

सोने के आयात पर दोनों देशों द्वारा आयात शुल्क को कम करने से सबसे ज़्यादा लाभ भारत के जूलरी सेक्टर को होने वाला है। भारत हर साल 200 टन तक के सोने के आयात पर कम आयात शुल्क लेने पर सहमत हो गया है। भारत ने 2020-21 में यूएई से क़रीब 70 टन सोने का आयात किया था। हालांकि, कई सेक्टरों को इस समझौते के नुक़सान से बचाने के लिए इस समझौते से बाहर रखा गया है।

ऐसे क्षेत्रों में डेयरी, फल, सब्ज़ियां, अनाज, चाय, कॉफ़ी, चीनी, तंबाकू, कोक, प्राकृतिक रबर, टायर, फुटवियर, खिलौने, प्लास्टिक, एल्युमीनियम और तांबे के स्क्रैप, चिकित्सा उपकरण, ऑटो और ऑटो के कल पुर्जे आदि शामिल हैं। हालांकि इन्हें प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा।

इस समझौते के मुख्य बिंदु

नए व्यापार, निवेश और इनोवेशन डायनेमिक्स की विकास गति तेज़ करने के लिए इस समझौते के संयुक्त विज़न स्टेटमेंट ने दोनों देशों के संबंधों के भविष्य की दिशा तय कर दी है।

1. आर्थिक साझेदारी

आर्थिक साझेदारी के तहत यूएई के जेबेल अली फ्री जोन में डेडिकेटेड इंडिया मार्ट की स्थापना होगी तो भारत में यूएई की कंपनियों के लिए एक डेडिकेटेड इनवेस्टमेंट ज़ोन बनाया जाएगा। साथ ही एक ज्वाइंट फूड कॉरिडोर भी बनाने पर सहमति बनी है। यूएई के अबू धाबी में लॉजिस्टिक्स और सर्विसेज़, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, कृषि, एग्रीटेक, स्टील और एल्युमीनियम जैसे क्षेत्रों में उद्योगों के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी ज़ोन बनाए जाएंगे, जहां भारतीय निवेशकों के लिए निवेश के नए मौक़े बनेंगे।

2. रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र

समुद्र के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाए जाएंगे, डिफ़ेंस के क्षेत्र में लेन-देन जारी रहेगा, अनुभवों को साझा किया जाएगा, प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास होते रहेंगे। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर ''चरमपंथ और आतंकवाद के साथ सीमा पार से चलाए जाने वाले और आतंकवाद'' से मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया है।

3. ऊर्जा साझेदारी

भारत यूएई के अहम ऊर्जा कारोबार साझेदारों में से एक है। समझौते के तहत यूएई ने भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग पूरी करने के लिए सहयोग देने का वचन दिया है। भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम में निवेश करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय साझेदार यूएई ही होगा। इस समझौते में ऊर्जा के उपयोग में हो रहे बदलाव का समर्थन करते हुए 'लो कार्बन फ़्यूचर' के लिए मिलकर काम करने पर सहमति दी गई है।

4. जलवायु परिवर्तन रोकने के प्रयास और ग्रीन एनर्जी

ऊर्जा उपयोग में हो रहे बदलाव और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के पालन के लिए एक दूसरे के स्वच्छ ऊर्जा मिशनों का समर्थन किया जाएगा। साथ ही संयुक्त हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी, ताकि नई तकनीकों की खोज हो सके। इस मामले में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. टेक्नोलॉजी

अहम टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा. ई-कॉमर्स और ई-पेमेंट सॉल्यूशंस को दोनों देश बढ़ावा देंगे। इसके अलावा, फ़िनटेक, एडुटेक, हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, एग्रीटेक, चिप डिज़ाइन और ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दोनों देशों के स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा। यूएई में भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान आईआईटी की स्थापना की जाएगी।

6. कौशल सहयोग

यूएई के श्रम बाज़ार के लिए कुशल लोगों की ज़रूरत को भारत से पूरा किया जाएगा। इसके लिए दोनों देश आपसी सहमति से पेशेवर मानक और कौशल ढांचे का विकास करेंगे।

7. स्वास्थ्य सहयोग

टीकों की आपूर्ति बेहतर करने और भारत के हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहयोग देने के लिए यूएई अनुसंधान, उत्पादन और विकास के कामों में अपना निवेश बढ़ाएगा। वंचित देशों की स्वास्थ्य ज़रूरतें पूरी करने के लिए सहयोग देने पर भी सहमति देनों देशों के बीच बनी है।

रूस को चीन से मिल रही ताकत, इस कारण पश्चिमी प्रतिबंधों की नहीं कर रहा परवाह!

मॉस्को। एजेंसी

रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले की आशंकाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के साथ ही हो गया है। रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पश्चिम देशों की आशंका के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच अमेरिका और कनाडा की ओर से रूस को लेकर कई प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। उधर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने मंगलवार को कहा कि उनके देश ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के प्रमाणन की प्रक्रिया को रोकने के लिए कदम उठाए हैं, क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन संकट के मद्देनजर रूस के खिलाफ दंडात्मक उपाय कर रहे हैं। यह फैसला जर्मन सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी आलोचना रूस ने की है। लेकिन रूस को चीन से अब मदद मिल रही है।

इस पाइपलाइन के जरिये रूस से यूक्रेन और पोलैंड के रास्?ते बाल्टिक सागर से जर्मनी को गैस भेजने की योजना थी। हालांकि अब विशेषज्ञ ऐसी संभावना जता रहे हैं कि पुतिन को यूरोपीय देशों और अमेरिका से मिल प्रतिबंधों के बाद

भी एक लाइफलाइन मिल सकती है, जो उनकी परेशानियां कम कर सकेगी। दरअसल कुछ दिन पहले रूस ने चीन के साथ एक समझौता किया था। इसके तहत रूस अगले 30 साल तक चीन को गैस उपलब्ध कराएगा। इस समझौते के तहत रूस समर्थित ऑयल कॉरपोरेशन गैजप्रोम ने चीन की बड़ी कंपनी सीएनपीसी को हर साल 10 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई करने की हामी भरी है। रूस के एक विशेषज्ञ का कहना है कि पुतिन और रूस के लिए यह डील काफी सहायक होगी। 117 अरब अमेरिकी डॉलर के रूसी तेल और गैस को चीन भेजने के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर कोई आक्रमण होता है तो यह समझौता मास्को को रूस से यूरोप तक नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रोकने के अमेरिकी खतरों से संभावित नतीजों को कम करने में मदद देता है।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चीन और रूस के बीच हुए इन समझौतों के कारण 2050 तक रूस चीन का सबसे बड़ा सप्लायर बन सकता है। रूस की रोजनेफ्ट कंपनी के कुल तेल उत्पादन का 25 फीसदी हिस्सा अब चीन के पास जा सकता है। वैसे रूस पहले से ही चीन को गैस सप्लाई कर रहा है। यह सप्लाई सर्बिया पाइपलाइन के जरिये 2019 में शुरू हुई थी। इसके साथ ही रूस लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) को समुद्र के रास्ते चीन भेज रहा है।

वास्तु शास्त्र और उसका परिस्थिति अनुसार बदलाव

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

वास्तु ऊर्जा का प्रभाव परिस्थित अनुसार बदलता है कॉलोनी डेवेलोप होने से छोटे मकान बनने तक कैसे परिवर्तन आता जाता है समझने का प्रयास करते हैं । जब कोई डेवलपर किसी कॉलोनी के लिए जमीन खरीदता है तभी से इस जमीन की वास्तु ऊर्जा का प्रभाव उस डेवलपर पर शुरू हो जाता है अर्थात एक जमीन पर शास्त्र के जो जो नियम लागू होते हैं उस डेवलपर पर कार्य करना शुरू कर देते हैं जैसे जमीन का आकार, ढलान,शल्य,जमीन पर छोटे बड़े टीले, जमीन में मौजूद कुँए बोरिंग आदि जलाशय,कोई जिओपेथी ऊर्जा या उसका नोडल पॉइंट,जमीन में मौजूद कोई मंदिर मजार वृक्ष (पीपल,बरगद,नीम आदि),बांबी आदि की ऊर्जा आदि सबका मिलाजुला प्रभाव शुरू हो जाता है । जब इस भूमि पर डेवलपर द्वारा विकास कार्य या निर्माण शुरू किया जाता है तब निर्माण संबंधी नियम लागू होना शुरू होते जाते हैं बाउंड्री वाल से एक सीमा सुनिश्चित हो जाती है दीवार की दिशा अनुसार ऊंचाई मोटाई का प्रभाव होने लगता है

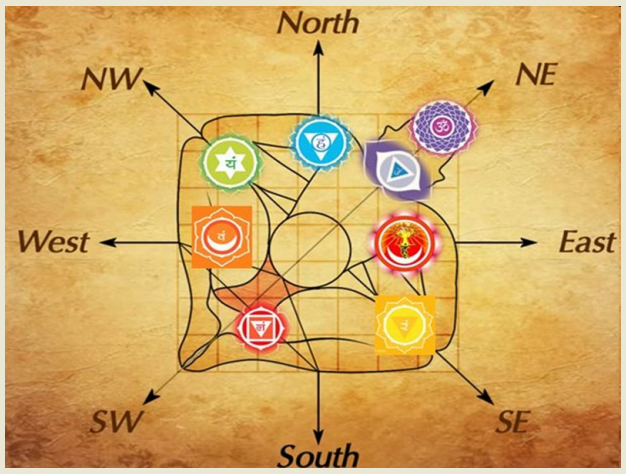

मुख्य द्वार की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होती है गलत पद में मुख्य द्वार का निर्माण डेवलपर के लिए तो परेशानी पैदा करता ही है आने वाले समय मे रहवासियों पर भी इसका परिणामिक प्रभाव देखने मे मिलता है.ठीक इसी प्रकार अन्य निर्माण जैसे भूमि के ढलान,सड़कों के ढलान,सेप्टी टैंक,पानी की टंकी,गार्डन,गार्डन आदि में स्थापित सांकेतिक मूर्तियाँ,ड्रेनेज की व्यवस्था , बिजली की अ्ङ की व्यवस्था आदि सब शास्त्र अनुसार होना लाभकारी होता है यदि निर्माण में शास्त्र अनुसार दोष छोड़े जाएँ तो शुरुवाती समय मे डेवलपर संबंधित दोषों के प्रभाव में रहता है फिर जैसे तैसे जब रहवासी उसमें आने लगते हैं तब सम्पूर्ण कॉलोनी के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अलग अलग रहवासियों पर भाग्य अनुसार होता है रहवासी पर दो रूपों में वास्तु ऊर्जा काम करती है पहली सम्पूर्ण कॉलोनी की ऊर्जा का प्रभाव और दूसरा मुख्य प्रभाव उसके निजी प्लाट या घर का होगा यहाँ अलग-अलग परिस्थिति पर विचार किया जा सकता है ।

1.वास्तु सम्मत बनी कॉलोनी में वास्तु सम्मत बना भवन अधिकतम समृद्धि प्रदान करेगा ।

2.दोषित कॉलोनी में वास्तु सम्मत बना भवन मिलाजुला प्रभाव देगा वह निर्भर करेगा कि कॉलोनी के किस दोषपूर्ण हिस्से में उसका भवन है.

3.यदि कॉलोनी दोषपूर्ण है और निर्मित भवन भी दोषपूर्ण है तब अधिकतम परेशानी.

4. शास्त्र नियम से बनी कॉलोनी है और उस पर दोषपूर्ण भवन का निर्माण किया गया है तब भी उपयोगकर्ता को विविध परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पूर्व में ही बताया है बड़ा प्रभाव भवन का है ।

यदि पॉइंट नंबर 1 अनुसार भवन मिल जाये तो सर्वोत्तम है परंतु ऐसा ना भी हो तो कम से कम आप अपने निजी जमीन पर नियमों का अधिकतम पालन कर प्राकृतिक ऊर्जाओं का अधिकतम उपयोग कर ही सकते हैं।

भगवान शिव को भी समर्पित है नवरात्रि

यहां होता है शिवनवरात्रि का अनूठा उत्सव

हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। शिव भक्त को पूरे साल इसका इंतजार रहता है। इस दिन शिव मंदिरों में पूजा और अभिषेक होता है। खास मंदिरों में इस उत्सव की खास धूम रहती है। इसे देखने और भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं। इन्हीं में से एक उज्जैन का महाकार मंदिर है। भोलेनाथ और माता पर्वती के विवाह का पर्व महाशिवरात्रि यहां बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि से पहले ही यहां कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं।

9 दिन मनाते हैं शिवनवरात्रि

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि से 9 दिन पहले ही उत्सव शुरू हो जाता है। यहां नौ दिनों तक शिवनवरात्रि मनाई जाती है। इस वर्ष 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। 21 फरवरी से शिवनवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। खास बात यह है कि शिवनवरात्रि का आयोजना पूरे देश में सिर्फ उज्जैन में होता है।

9 रूपों में होता है ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार

शिवनवरात्रि के दौरान महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 9 दिनों तक भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। सिर्फ मंदिर के पुजारी ही पूजा करते हैं। नौ दिनों तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को 9 अलग-अलग रूपों में सजाया जाता है। पहले दिन श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भांग, सूखे मेवे, फल-फूल और रेशमी वस्त्रों से किया जाता है। दूसरे दिन श्री शेषनाग श्रृंगार, तीसरे दिन घटाटोप श्रृंगार, चौथे दिन श्री छबीना श्रृंगार, पांचवे दिन श्री होलकर श्रृंगार, छठवें दिन श्री मनमहेश श्रृंगार, सातवें दिन श्री उमामहेश श्रृंगार, आठवें दिन श्री शिवतांडव श्रृंगार, और नौवें दिन पूरे गर्भगृह को फूलों से सजाया जाता है। साथ ही भगवान शिवजी का विवाहोत्सव मनाया जाता है।

10वां दिन होता है खास

महाशिवरात्रि के दिन शिव-पार्वती विवाह समारोह की परंपरा निभाने के बाद भगवान का श्री सेहरा श्रृंगार किया जाता है। जिसमें सवामन पुष्पों से सेहरा बनाकर भोलेनाथ को पहनाया जाता है। इस दिन भस्मा आरती ब्रहमुहूर्त में ना होकर विशेष मुहूर्त में दोपहर के समय की जाती है।

महाशिवरात्रि पर बन रहा मनोकामना पूरी होने का योग, अप्रत्याशित लाभ मिलेगा

हिंदू धर्म में शिव नवरात्रि मनाने की विशेष तौर पर परंपरा है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। इस दिन पांच राशि वाले बेहद किस्मत वाले रहेंगे। इन पर भगवान शिवजी की विशेष कृपा रहेगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी मनोकामना पूरी होंगी। आइए जानते हैं किन राशियों के अच्छे दिन शुरू होंगे। महाशिवरात्रि पर यूं तो दिन भर भगवान भोले की पूजा-अचर्ना की जा सकती है, लेकिन रात्रि में पूजा का विशेष महत्व है। शिवरात्रि पूजा रात में एक या चार बार की जा सकती है। पूरी रात की अवधि को चार प्रहरों में बांटा गया है। इस दिन ध्यान करने की सलाह दी जाती है और पूरे दिन में जितनी बार संभव हो 'ओम नमः शिवाय' का जाप करें।

मेष राशि : मेष राशिवालों के लिए महाशिवरात्रि का दिन खास रहेगा। मनोकामना पूरी होने के योग बनेंगे। करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। परिवार में सुख शांति पूर्ण माहौल रहेगा।

वृषभ राशिः वृषभ राशि के जातकों को धन की प्राप्ति हो सकती है। नजदीकी संबंधियों के साथ मुलाकात के अवसर बनेंगे। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर घी और शमी के पत्ते चढ़ाने से लाभ होगा।

मिथुन राशि : मिथुन राशिवालों के लिए

महाशिवरात्रि का त्योहार खुशियां लेकर आएगा। इस दिन शुभ समाचार मिल सकता है। किसी शुभचिंतक की प्रेरणा और आशीर्वाद शुभ साबित होगा।

सिंह राशि : सिंह राशि वालों को अच्छा खबर प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुछ नए संपर्क स्त्रोत बनेंगे, जो आगे फायदेमंद रहेंगे। भगवान शिवजी की कृपा पाने के लिए दूध में घी और केसर मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करें।

कर्क राशिः कर्क राशिवालों को महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। किसी पुराने निवेश से बहुत अधिक मुनाफा होगा। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे।

महाशिवरात्रि की पूजा विधि

महाशिवरात्रि के दिन व्रत का संकल्प करके पूजा घर में शिवलिंग और मां पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। श्रद्धा-भाव से पूजा करें।

पूजा में पंचामृत, मोली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, बेल-पत्र आदि अर्पित करें।

शिवाष्टक, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टक का पाठ करें।

महाशिवरात्रि पूजन सामग्री लिस्ट

भगवान शिव की पूजा में गंगा जल और धतूरे का विशेष महत्व है। इसके अलावा सुगंधित पुष्प, पंच फल पंच मेवा, पंच रस, इत्र, गंध रोली, मौली जनेऊ, पंच मिष्ठान्न, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बालें,तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रूई, मलयागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, वस्त्राभूषण रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद जरूर शामिल करें।

भगवान शिव को कैसे हुई त्रिशूल की प्राप्ति

हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है और देशभर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए विशेष आयोजन किए जाते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व 01 मार्च 2022 को है। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इसी दिन भगवान शिव ने साकार रूप धारण किया था। मान्यता है कि इससे पहले वे परब्रह्म सदाशिव थे।

भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है त्रिशूल

भगवान शिव को स्मरण करते ही हाथों में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव की विशाल प्रतिमा, उनके गले में एक डमरू, एक सिर, एक सांप दिखाई देने लगता है। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है। कालों के काल महाकाल भगवान शिव का समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भोलेनाथ का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के पास त्रिशूल कैसे आया? इसका अर्थ और महत्व क्या है?

भगवान शिव के त्रिशूल का रहस्य

शिव पुराण में भगवान शिव के त्रिशूल को लेकर एक पौराणिक कथा का जिक्र किया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि पूरी सृष्टि की शुरुआत के समय भगवान शिव ब्राह्मणाद से प्रकट हुए थे। उनके साथ तीन गुण, रज, तम और सत गुण भी प्रकट हुए, इन तीनों गुणों को मिलाकर शिव शूल बने, जिससे त्रिशूल बना। जबकि विष्णु पुराण में बताया गया है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के उस हिस्से से एक त्रिशूल बनाया था, जिसे उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया था।

रज, तम और सत गुणों के संतुलन से सृष्टि का संतुलन

सांख्य दर्शन के अनुसार भी मान्यता है कि रज, तम और सत गुणों के बीच संतुलन के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता था। इन तीन गुणों में ही भगवान शिव मग्न रहते हैं। त्रिशूल में ये तीन गुण शामिल हैं। इसके साथ ही महादेव के त्रिशूल को भी तीन काल खंडों से जोड़कर देखा जाता है।

एसईए ने खाद्य तेल कंपनियों से खुदरा मूल्य में कमी करने को कहा

नयी दिल्ली। एजेंसी

उद्योग संगठन एसईए (सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) ने सोमवार को अपने सदस्यों से अपील की कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वे तत्काल प्रभाव से खाद्यतेल के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में 3-5 रुपये की कमी करें। वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में कमी का कोई संकेत नहीं आने की बात कहते हुए संगठन ने यह अपील की। यह दूसरा मौका है जब उद्योग निकाय एसईए ने अपने सदस्यों से एमआरपी में कटौती करने का अनुरोध किया है। पिछली बार, इसने अपने सदस्यों को नवंबर 2021 में दिवाली के आसपास खाद्य तेलों के एमआरपी में 3-5 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी करने के लिए कहा था।

भारत अपने खाद्य तेलों की 60 प्रतिशत से अधिक की मांग को आयात के माध्यम से पूरा करता है। भारत ने खाद्यतेलों की खुदरा कीमतों पर अंकुश रखने के लिए पिछले कुछ महीनों में पाम तेल पर आयात शुल्क घटाने, स्टॉक सीमा लागू करने जैसे विभिन्न कदम उठाये थे। सरकार के इन सक्रिय प्रयासों के बावजूद, अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतें एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में अधिक बनी हुई हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा, 'इन कीमतों में नरमी के कोई तत्काल संकेत नहीं दिख रहे हैं और इंडोनेशिया जैसे कुछ निर्यातक देशों ने

भी लाइसेंस के जरिए पाम तेल के निर्यात को विनियमित करना शुरू कर दिया है।' वैश्विक खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और यह 'आयातित मुद्रास्फीति' न केवल सभी अंशधारकों बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी परेशान कर रही है। इसके अलावा, रूस और यूक्रेन के बीच काला सागर क्षेत्र में तनाव उस क्षेत्र से आने वाले सूरजमुखी तेल के लिए आग में घी डालने का काम कर रहा है। ला नीना के कारण ब्राजील में खराब मौसम ने भी लैटिन अमेरिका में सोया की फसल को काफी कम कर दिया है। इस वैश्विक स्थिति को देखते हुए, एसईए ने कहा कि हालांकि इसके सदस्य खाद्य तेलों की सुचारू आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं, वे सरकार के सक्रिय निर्णयों के साथ जुड़े हुए हैं।

एसईए ने कहा कि उसने 'अपने सदस्यों से अनुरोध किया है और उन्हें सलाह दी है कि कीमतों में नरमी के लिए तत्काल प्रभाव से खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य में 3,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति टन (3 से 5 रुपये प्रति किलोग्राम) की कमी करें।'

उद्योग संगठन ने यह भी उल्लेख किया कि घरेलू सरसों की फसल काफी बेहतर है और यह चालू वर्ष के दौरान रिकॉर्ड फसल की उम्मीद की जा रही है जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। इसके अलावा, सरकार नई सरसों की फसल बाजार में आने से पहले कीमतों को नरम करने के लिए त्वरित कदम उठाने में सक्रिय रही है। कच्चे पाम तेल (सीपीओ) पर आयात शुल्क में हाल ही में 2.5 प्रतिशत की कमी इसका एक उदाहरण है। एसईए ने कहा, 'हमारे एसईए सदस्यों के इस छोटे से होली उपहार से हमारे उपभोक्ताओं को राहत मिलने और त्यौहार में कुछ रंग जोड़ने में मदद मिलेगी।' उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा रखे जाने वाले आंकड़ों के अनुसार, मूंगफली तेल (पैक) का औसत खुदरा मूल्य 20 फरवरी को 177.75 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो एक साल पहले की अवधि में 164.55 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक था। इसी तरह, सरसों तेल (पैकबंद) का खुदरा मूल्य इस साल 20 फरवरी को 187.03 रुपये प्रति किलोग्राम था, जबकि 2021 के समान दिन में 145.02 रुपये प्रति किलोग्राम था, जबकि सोया तेल (पैकबंद) का खुदरा मूल्य 147.36 रुपये प्रति किलोग्राम था जो पिछले साल इसी समय 126.03 रुपये प्रति किलो था। आंकड़ों से पता चलता है कि सूरजमुखी तेल की खुदरा कीमत भी 144.22 रुपये प्रति किलोग्राम के मुकाबले 161.75 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि पाम तेल की कीमत 130.53 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि पिछले साल इसी दौरान यह 113.89 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

News यू केन USE

अंतरराष्ट्रीय सेवाएं सामान्य होने के बाद मुंबई हवाईअड्डा रोजाना 'संभालेगा' 1,000 उड़ानें

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

अंतरराष्ट्रीय सेवाएं सामान्य होने के बाद मुंबई हवाईअड्डा रोजाना 1,000 से अधिक उड़ानें संभालेगा। यानी यहां से प्रतिदिन 1,000 से अधिक विमान रवाना होंगे या उतरेंगे। एटीसी गिल्ड ने यह बात कही है। फिलहाल देश के दूसरे सबसे बड़े हवाईअड्डे पर हवाई यातायात

कोविड-पूर्व स्तर से करीब 25 प्रतिशत कम है। सात जून, 2018 को इस हवाईअड्डे पर विमानों की आवाजाही का आंकड़ा 1,003 था। एटीसी गिल्ड (इंडिया) के क्षेत्रीय सचिव सैफुल्लाह ने कहा कि मार्च, 2020 में महामारी से पहले इस हवाईअड्डे पर प्रतिदिन 950 विमान आ रहे थे। फिलहाल यह संख्या घटकर 700 से कुछ अधिक है। सैफुल्लाह ने हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) के परिचालन के 100 साल पूरे होने के मौके पर संवाददाताओं से कहा, ''अभी यहां प्रतिदिन 700 विमानों की आवाजाही है। यह महामारी-पूर्व के स्तर से अभी 25 प्रतिशत कम है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें काफी कम हैं और इसमें अधिक हिस्सेदारी घरेलू उड़ानों की है।'' उन्होंने कहा कि नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जल्द शुरू होंगी। ''निश्चित रूप से उस समय हम नियमित रूप से प्रतिदिन 1,000 उड़ानों को संभालेंगे।''

यूक्रेन और रूस के बीच विवाद में अब जापान भी शामिल

रूसी नागरिको की संपत्ति फ्रीज की

नई दिल्ली। एजेंसी

यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर कई नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमला करते हुए कहा है कि वे खुद को भगवान ने समझे। इस बीच इस रूस और यूक्रेन के विवाद में अब जापान की भी एंट्री हो गई है। जापान ने अमेरिका और ब्रिटेन का साथ देते हुए अपने देश में कई रूसी नागरिकों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।

जापान ने रूस पर भी लगाया प्रतिबंध

रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद में अब जापान भी कूद गया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बुधवार को कहा कि जापान रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें जापान में रूसी बांड जारी करने पर प्रतिबंध और कुछ रूसी व्यक्तियों की संपत्ति को फ्रीज करना शामिल है।

यूक्रेन बोले, जब तक जीतेंगे नहीं, तब तक लड़ते रहेंगे

रूसी कार्रवाई के खिलाफ अब यूक्रेन भी सख्त हो गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबास ने कहा है कि मामूली, मध्यम या बड़े हमले जैसी कोई बात नहीं है। एक हमला भी हमला ही होता है। हम कूटनीतिक और सैन्य दोनों विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। कुलेबास ने कहा कि हम अपनी जमीन के हर इंच और हर शहर और हर गांव के लिए लड़ना है, हम तब तक लड़ेंगे, जब तक हम जीतेंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रही, यह रफ्तार बरकरार रहने की उम्मीदः अमिताभ कांत

नयी दिल्ली। एजेंसी

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है और आने वाले वर्षों में भी वृद्धि की यह रफ्तार बरकरार रहने की उम्मीद है। सरकार के उभरते क्षेत्रों के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का जिक्र करते हुए कांत ने कहा कि इससे अगले पांच साल में देश के उत्पादन में 520 अरब डॉलर का इजाफा होगा और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनेगा। कांत ने एआईएमए (ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन) के एक कार्यक्रम में कहा, ''भारत आज अभूतपूर्व स्तर के आर्थिक विकास और तकनीकी बदलावों को देख रहा है। अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है और आने वाले वर्षों में भी वृद्धि की यह रफ्तार बरकरार रहने की उम्मीद है। इसके साथ हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाले देशों में से एक हैं।'' उन्होंने कहा कि देश ने दक्षता को अधिकतम करने के लिए कई उपाय किये हैं। सरकार ने इसके लिये कई सुधार किये हैं, जिसमें जीएसटी (माल एवं सेवा कर), दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता, कॉरपोरेट करों को कम करना आदि शामिल हैं।

नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि इससे भारत को दुनिया में विनिर्माण के क्षेत्र में चैंपियन बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ढांचागत क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिये राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा संपत्ति मौद्रिकरण पाइपलाइन और पीएम गतिशक्ति जैसे योजनाएं शुरू की है। कांत ने कहा, ''इन दोनों योजनाओं के संयुक्त प्रभाव से देश में सरकार और निजी क्षेत्र-दोनों की भागीदारी से वैश्विक स्तर की ढांचागत परियोजनाएं तैयार होंगी।'' उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में सफलता के लिये प्रौद्योगिकी को अपनाना जरूरी है। भारत पहले ही प्रौद्योगिकी के लिये एक उपयुक्त परिवेश तैयार करने में सफल रहा है। आज देश में 81.4 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता और 85 यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप) हैं।

भारतः विदेशी मुद्रा भंडार 1.76 अरब डॉलर घटकर 630.19 अरब डॉलर रहा

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) भंडार 11 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 1.763 बिलियन डॉलर घटकर 630.19 बिलियन डॉलर हो गया, जो कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के मूल्य में तेज गिरावट के कारण है। आरबीआई के साप्ताहिक सांख्यिकीय पूरक के अनुसार, विदेशी मुद्रा संपत्ति, जो विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है, समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान 2.764 डॉलर बिलियन से 565.565 बिलियन डॉलर तक गिर गया। आईएमएफ में भारत की रिजर्व पोजीशन 1.6 करोड़ डॉलर घटकर 5.217 अरब डॉलर रह गई। हालांकि, सोने के भंडार और

एसडीआर के मूल्य में तेज वृद्धि हुई। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान सोने के भंडार का मूल्य 952 मिलियन डॉलर बढ़कर 40.235 बिलियन डॉलर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ भारत के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) का मूल्य 65 मिलियन डॉलर बढ़कर 19.173 अरब डॉलर हो गया।

इंसानी शरीर, गद्दे और कार्पेट: श्रीलंका ने ब्रिटेन को क्यों लौटाया 3,000 टन कचरा?

कोलंबो। एजेंसी

श्रीलंका ने सोमवार को हजारों टन अवैध रूप से आयातित कचरे से भरे कई सौ कंटेनरों में से आखिरी कंटेनरों के बेड़े को ब्रिटेन वापस भेज दिया। ये पहला मौका नहीं है जब किसी देश ने ऐसी कार्रवाई की है। इससे पहले भी कई एशियाई देश हाल के वर्षों में धनी देशों से कूड़ा करकट के हमले के खिलाफ जोर दे रहे हैं और अवांछित शिपमेंट को वापस करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीलंका ने सोमवार को ब्रिटेन से लाए गए क्लिनिकल कचरे, इस्तेमाल किए गए कुशन और गद्दे सहित खतरनाक कचरे वाले अंतिम 45 कंटेनरों को ब्रिटेन भेज दिया। कंटेनर 2019 में श्रीलंका में आयात किए गए 263 कंटेनरों का हिस्सा थे। एक स्थानीय कंपनी ने कहा कि कचरे को यूनाइटेड किंगडम से श्रीलंका लाया गया था। बेसल (BASEL) कन्वेंशन के तहत, यह दो देशों के बीच कचरे का आयात करने का सीधा उल्लंघन है, और इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय पर्यावरण प्राधिकरण और श्रीलंका कस्टम की पहल के तहत, 21 फरवरी, 2022 को यूके में अपशिष्ट सामग्री वाले शेष 45 कंटेनरों को फिर से निर्यात करने के लिए कार्रवाई की गई थी।

2019 में, श्रीलंका कस्टम के सोशल प्रोटेक्शन डिवीजन की एक जांच में 263 कंटेनर पाए गए जिनमें क्लिनिकल वेस्ट, इस्तेमाल किए गए कुशन और गद्दे, प्लास्टिक कचरा और ब्रिटेन से देश में आयात किए गए अनसोल्ड और खतरनाक अपशिष्ट थे। ब्रिटेन से कचरा 2017 और 2019 के बीच श्रीलंका पहुंचा और उसे 'इस्तेमाल किए गए गद्दे, कालीन और कुशन' के रूप में बताया गया था। लेकिन असल में इसमें अस्पतालों का बायोवेस्ट भी शामिल था, जिसमें सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार शव, व शव के शरीर के अंग भी शामिल थे। कंटेनरों को ठंडा रखने का कोई तरीका नहीं था जिसके चलते उनमें से कई बहुत गंदी बदबू छोड़ने लगे थे। कुछ समय पहले ये खुलासा हुआ था कि 133 कंटेनरों को कोलंबो के बंदरगाह पर रखा गया था और शेष 130 कंटेनरों को पहले ही बंदरगाह से हटा दिया गया था और कटुनायके में निवेश बोर्ड (बीओआई) के तहत संचालित एक निजी कंपनी के परिसर में रखा गया था। कस्टम की जांच के दौरान, पर्यावरण न्याय केंद्र ने कोर्ट ऑफ अपील में एक मामला दायर किया। उस मामले के परिणामस्वरूप, कोर्ट ऑफ अपील ने एक आदेश जारी किया कि 263 कंटेनरों को तत्काल प्रभाव से ब्रिटेन वापस भेजा जाए। जिसके बाद श्रीलंका के सीमा शुल्क ने कोलंबो बंदरगाह में निहित कचरे के 133 कंटेनरों को वर्ष 2020 तक ब्रिटेन भेजने के लिए कार्रवाई की। इसके अलावा, श्रीलंका सीमा शुल्क ने कटुनायके में निजी कंपनी परिसर में रखे गए 130 कंटेनरों को सुरक्षित किया और पिछले वर्ष के दौरान नौ अवसरों पर ब्रिटेन को 85 कंटेनरों का पुनः वापस भेज दिया। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय पर्यावरण प्राधिकरण ने इन कंटेनरों के प्रत्यावर्तन को सफल बनाने के लिए शुरू से ही श्रीलंका के कस्टम को बहुत सहायता प्रदान की। श्रीलंका कस्टम इस अवैध गतिविधि में शामिल व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ कस्टम अध्यादेश के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई करेगा।

क्या है बेसेल संधि?

बेसेल संधि (Basel Convention) खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमापार यानी एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अंतरराष्ट्रीय संधि यानी बेसल कन्वेंशन को देशों के बीच खतरनाक कचरे की आवाजाही को कम करने और विशेष रूप से विकसित से कम विकसित देशों में खतरनाक कचरे के हस्तांतरण को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था।

पांच साल में 100 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है कपड़ा निर्यात : सचिव

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश का वार्षिक कपड़ा निर्यात अगले पांच साल में मौजूदा 40 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। कपड़ा सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने यह बात कही है। सिंह ने कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) के 44वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि देश के परिधान उद्योग को अपने स्तर और आकार को बढ़ाने के लिए एकीकरण पर ध्यान देना चाहिए और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लाभ उठाना चाहिए। इस कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कपड़ा या परिधान बहुत अधिक निवेश केंद्रित क्षेत्र नहीं है लेकिन रोजगार की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना के साथ सरकार पीएम मित्र (प्रधानमंत्री वृहत एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान) योजना को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नए सीएसआर खुलासा ढांचे से डेटा विश्लेषण में मदद मिलेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर खर्च के लिए नए खुलासा या प्रकटीकरण ढांचे से विश्लेषणात्मक कार्यों में मदद मिलेगी और खर्च के संबंध में अधिक पारदर्शिता आएगी। लाभप्रद कंपनियों के लिए सीएसआर व्यवस्था अप्रैल, 2014 में लागू हुई थी और 30 सितंबर, 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान इन कार्यों के लिए 8,828.11 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में खर्च की गई राशि 20,360 करोड़ रुपये है। हालांकि, यह आंकड़ा अधिक होने की संभावना है क्योंकि कॉरपोरेट के पास सीएसआर से संबंधित जानकारी देने के लिए मार्च तक का समय है। इस महीने की शुरुआत में मंत्रालय ने फॉर्म सीएसआर -2 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर रिपोर्ट को अधिसूचित किया। अधिकारी ने कहा कि फॉर्म की शुरुआत का मकसद सीएसआर खर्च के बारे में बारीक विवरण हासिल करना है, जो विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए जरूरी है। इससे हितधारकों को यह जानने में भी मदद मिलेगी कि कंपनियां अपने सीएसआर दायित्वों के साथ क्या कर रही हैं। यह फॉर्म मशीन पठनीय प्रारूप में होगा और इसका डेटा सीएसआर पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। फॉर्म को लेकर यह चिंता भी जताई गई है कि नई प्रकटीकरण जरूरतों से कंपनियों के लिए अनुपालन बोझ बढ़ सकता है। अधिकारी ने कहा कि नई खुलासा आवश्यकताओं का मकसद कंपनियों की गतिविधियों में अधिक पारदर्शिता लाना है।

ई-कॉमर्स के जरिये आईजीसीआर और आभूषण निर्यात का मॉड्यूल -सीबीआईसी अध्यक्ष

नई दिल्ली। एजेंसी

फेडेरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) द्वारा निर्यात पर आम बजट 2022-23 का विश्लेषण तथा चर्चा करने के लिए आयोजित अखिल भारतीय वेबीनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष श्री विवेक जोहरी ने कहा कि हमें यह देख कर प्रसन्नता हुई कि महामारी के बाद निर्यात में फिर से तेजी आ गई है और उन्होंने निर्यातक समुदाय की उनकी कड़ी मेहनत के लिए प्रशंसा की।

सीबीआईसी अध्यक्ष ने बताया कि रियायती नियमों पर वस्तुओं के आयात के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल (आईजीसीआर) अग्रिम चरण में है और 1 मार्च, 2022 से कार्यान्वित किया जाएगा। यह निर्यातकों को बिना किसी भौतिक हस्तक्षेप के शुल्क-मुक्त वस्तुओं की मंजूरी में सहायता करेगा। श्री जोहरी ने कहा कि सरकार ई-कॉम के जरिये आभूषणों के निर्यात को सुगम बनाएगी जिसके लिए एक 'सरलीकृत नियामकीय ढांचा' पर काम किया जा रहा है जिसे जून 2022 तक प्रचालनगत किया जाएगा।

इस अवसर पर सीबीआईसी के सदस्य (सीमाशुल्क) श्री राजीव तलवार ने कहा कि सीमाशुल्क टैरिफ में नए सामंजस्यपूर्ण कोड का उपयोग हमें बेहतर तरीके से ड्राबैक तथा अन्य योजनाओं को लक्षित करने में सहायता करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाणिज्यिक डाटा के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया जाना समय की आवश्यकता थी क्योंकि डाटा के बाहर आने (लीकेज) से निर्यातक प्रभावित हो रहे थे। गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए फियो अध्यक्ष डॉ. ए शक्तिवेल ने वित्त मंत्रालय को ऐतिहासिक आम बजट 2022-23 के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बजट में डिजिटाइजेशन, डिस्टिलेशन तथा ऑटोमेशन पर फोकस के साथ व्यवसाय करने की सुगमता के विभिन्न प्रभाव हैं। फियो अध्यक्ष ने कहा कि अब जबकि सारा फोकस आत्म निर्भर भारत पर है, विकास के सभी चार स्तंभों- समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन, ऊर्जा रूपांतरण तथा जलवायु कार्रवाई को छुआ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रिमिंग तथा अलंकरण के रूप में अनुमति प्राप्त मदों की सूची का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है और आईटीसी उपलब्धता के नए नियमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक व्यवसायों को असुविधा न हो।

इससे पूर्व, फियो के महानिदेशक तथा सीईओ डॉ. अजय सहाय ने कहा कि इस वर्ष का आम बजट निवेश तथा अवसंरचना पर फोकस के साथ विकासोन्मुखी है। उन्होंने कहा कि कोलैटेरल-फ्री आपातकालीन क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम को पांच लाख करोड़ रुपये के बढ़े हुए कॉर्पस के साथ एक वर्ष और अधिक विस्तारित करने से छोटे व्यवसायों और विशेष रूप से आतिथ्य तथा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा जो कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। डॉ. सहाय ने उम्मीद जताई कि 2005 के एसईजेड अधिनियम को एक नए अधिनियम के साथ प्रतिस्थापित करने से एसईजेड स्कीम के योजना की निर्यात केंद्रित प्रकृति से हट कर और अधिक आर्थिक कांकलेव स्कीम बनने की उम्मीद है जहां निर्यात दायित्व पर बिना कोई जोर दिए घरेलू बाजार तथा निर्यात के बीच का अंतर कम हो जाता है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।